अध्याय XVIII : ग्रामीण विकास मंत्रालय

18.1 आंतरिक नियंत्रण विफलता के कारण दोहरा भुगतान

आंतरिक नियंत्रण जांच में विफलता के परिणामस्वरूप एक एजेंसी को ₹ 1.26 करोड़ का दोहरा भुगतान किया गया, जो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक पता नहीं चल सका।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने कुछ पूर्व और उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुरक्षा क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत एक विशेष परियोजना का अनुमोदन किया (नवंबर 2010)। परियोजना की ₹ 15 करोड़ की लागत थी, जिसमें से केंद्रीय अंश ₹ 11.25 करोड़ था, अर्थात 75 प्रतिशत थी। परियोजना में 7,860 लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए शामिल करना था जो संस्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नियुक्तियों के लिए अग्रणी होते हैं। एक सुरक्षा सेवा प्रशिक्षण अकादमी को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में चुना गया था, जो कि परियोजना लागत का 25 प्रतिशत वहन करेगी। परियोजना के लिए नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) थी।

मंत्रालय ने (जनवरी 2011) पीआईए को संवितरण के लिए टीएसए को ₹ 2.81 करोड़ पहली किस्त के रूप में जारी किये। केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त और दो वर्षों तक परियोजना के विस्तार के लिए जारी करने के लिए मंत्रालय ने टीएसए से प्रस्ताव प्राप्त किया (नवंबर 2012)। हालांकि, लक्ष्य के प्रति उपलब्धियों में कमी के कारण और परियोजना को पूरा करने के लिए अपर्याप्त समय शेष था, मंत्रालय ने जनवरी 2015 में इस परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया। काम के आधार पर और लक्ष्यों में कमी के लिए दंड समायोजित करने के बाद मंत्रालय ने पीआईए को टीएसए के माध्यम से ₹ 1.26 करोड़ का अंतिम भुगतान जारी किया (फरवरी 2015)।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2014-15 में निधियों की अनुपलब्धता के कारण संस्वीकृति के आदेश जारी नहीं किए गए, मंत्रालय ने

ई-ऑफिस के माध्यम से ₹ 1.26 करोड़ के अंतिम भुगतान को फिर से संसाधित किया था (मई 2015)। वित्त शाखा ने भी अपनी सहमति (मई 2015) को दोबारा वैध कर दिया था और मंत्रालय ने नए प्रतिबंधों को जारी कर दिया था, जिस पर ₹ 1.26 करोड़ फिर से टीएसए को जारी किए गए थे (जून 2015)। इस प्रकार, मंत्रालय ने इसी कार्य के लिए टीएसए को दो बार ₹ 1.26 करोड़ रूपये जारी किये।

लेखापरीक्षा द्वारा बताया जाने पर, मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया (फरवरी 2017 और अक्तूबर 2017) कि भुगतान दो बार अनजाने में जारी किया गया था। यह भी बताया कि टीएसए ने 25 जनवरी 2017 को ₹ 1.26 करोड़ वापस कर दिए थे। हालांकि, मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि वित्त शाखा ने दोनों निर्गमों की जांच के बावजूद दोहरे भुगतान कैसे किए और दोहरा भुगतान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक दो वर्षों से पता क्यों नहीं लग सका।

इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण जांच में विफलता के परिणामस्वरूप एक एजेंसी को ₹ 1.26 करोड़ रूपये का दोहरा भुगतान हुआ, जो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक पता नहीं चल सका।